

साप्ताहिक करंट अफेयर्स ३१ मई-४ जून 2021

Important News: State

असम के मुख्यमंत्री ने 'अभिभावक मंत्रियों' की नियुक्ति की

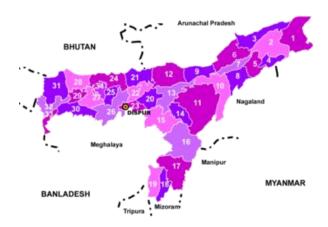
चर्चा में क्यों?

• असम के म्ख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने विभिन्न जिलों के लिए 'अभिभावक मंत्री' निय्क्त किए।



प्रमुख बिंदु

- इन अभिभावकों, प्रत्येक हिमंत बिस्वा सरमा कैबिनेट के मंत्री को, सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य की अपनी प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए 2-3 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है।
- 34 जिलों में सरकार के नीतिगत निर्णयों, प्रशासनिक सुधारों और जनता के लिए अन्य कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 13 मंत्री जिम्मेदार होंगे।



असम के बारे में तथ्य:

राज्य नृत्य: बिह् नृत्य

राज्य पक्षी: सफेद पंखों वाली बतख राज्य जानवर: एक सींग वाला गैंडा







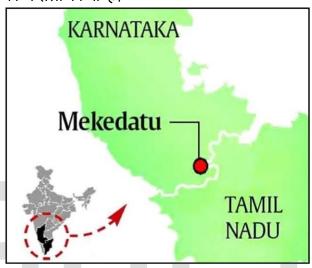
राज्य फूल: फॉक्सटेल ऑर्किड

राज्य वृक्षः हॉलोंग

मेकेदात् परियोजना

चर्चा में क्यों?

• हाल ही में, कर्नाटक सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा कावेरी नदी पर बांध के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल मेकेदातु में कथित उल्लंघनों को देखने के लिए एक समिति का गठन किया है, के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है।



प्रमुख बिंदु समिति के बारे में:

• नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कर्नाटक में मेकेदातु में कावेरी नदी पर एक जलाशय के निर्माण में मानदंडों के कथित उल्लंघन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया है।



मेकेदात् परियोजना

- यह एक बहुउद्देश्यीय (पीने और बिजली) परियोजना है, जिसमें रामनगर जिले के कनकपुरा के पास एक संतुलन जलाशय का निर्माण शामिल है।
- एक बार पूरी होने वाली परियोजना का उद्देश्य बेंगलुरु और पड़ोसी क्षेत्रों (4.75 TMC) को पीने का पानी







सुनिश्चित करना है और 400 मेगावाट बिजली भी पैदा कर सकता है, और परियोजना की अनुमानित लागत 9,000 करोड़ रुपये है।

- यह पहली बार 2017 में कर्नाटक सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) से अनुमोदन महत्वपूर्ण है क्योंकि कावेरी वन्यजीव अभयारण्य का 63% वन क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा।

नोट: 2018 में, तमिलनाडु ने परियोजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, भले ही कर्नाटक ने माना हो कि यह तमिलनाड् में पानी के प्रवाह को प्रभावित नहीं करेगा।

तमिलनाड् द्वारा विरोध के कारण:

- तमिलनाडु ऊपरी तट पर प्रस्तावित किसी भी परियोजना का विरोध करता है जब तक कि इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।
- कर्नाटक को इस मामले में निचले तटवर्ती राज्य यानी तमिलनाडु की सहमित के बिना अंतर-राज्यीय नदी पर कोई जलाशय बनाने का कोई अधिकार नहीं है।
- यह परियोजना कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT) के अंतिम आदेश के खिलाफ है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कोई भी राज्य विशेष स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है या अन्य राज्यों को अंतर-राज्यीय नदियों के पानी से वंचित करने के अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है।

कावेरी नदी

- कावेरी एक भारतीय नदी है जो कर्नाटक और तमिलनाड़ राज्यों से होकर बहती है।
- यह दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है और तमिलनाडु राज्य में सबसे बड़ी है।

विवाद:

• चूंकि नदी कर्नाटक से निकलती है, केरल से आने वाली प्रमुख सहायक नदियों के साथ तिमलनाडु से होकर बहती है और पुडुचेरी से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए विवाद में 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है।

हाल के घटनाक्रम:

- सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला 2018 में आया जहां उसने कावेरी को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया और CWDT द्वारा अंतिम रूप से जल-बंटवारे की व्यवस्था को बरकरार रखा और कर्नाटक से तमिलनाडु को पानी के आवंटन को भी कम कर दिया।
- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, कर्नाटक को 284.75 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (tmcft), तमिलनाडु को 404.25 tmcft, केरल को 30 tmcft और प्ड्चेरी को 7 tmcft मिलेगा।
- इसने केंद्र को कावेरी प्रबंधन योजना को अधिसूचित करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने 'कावेरी जल प्रबंधन योजना' जून 2018 में अधिसूचित की, जिसमें 'कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण' और 'कावेरी जल विनियमन समिति' का गठन किया गया।







मध्य प्रदेश सरकार ने 'अंकुर' योजना की शुरुआत की

चर्चा में क्यों?

 मध्य प्रदेश सरकार ने मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए लोगों को पुरस्कृत करने के लिए 'अंकुर' योजना शुरू की।

पौधरोपण की पहल करने वाले लोगों को उनकी भागीदारी के लिए प्राणवाय प्रस्कार दिया जाएगा।



प्रमुख बिंदु

'अंक्र' योजना के बारे में:

- यह योजना कार्यक्रम में जनता की भागीदारी स्निश्चित करेगी।
- जो लोग वृक्षारोपण अभियान में भाग लेना चाहते हैं, वे वायुदूत ऐप पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
- प्रतिभागियों को पौधा लगाते समय एक तस्वीर अपलोड करनी होगी और 30 दिनों तक पौधे की देखभाल करने के बाद दूसरी तस्वीर अपलोड करनी होगी।
- सत्यापन के बाद म्ख्यमंत्री प्रत्येक जिले से चयनित विजेताओं को प्राणवाय प्रस्कार प्रदान करेंगे।

Important News: India

आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिट्री पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप

चर्चा में क्यों?

• आयुष मंत्रालय ने वर्चुअल आयोजन में आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिट्री पोर्टल (ACCR) पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप का तीसरा संस्करण लॉन्च किया।









आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल के बारे में:

- यह आयुष चिकित्सकों और आम जनता दोनों का समर्थन करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा।
- इस पोर्टल का उद्देश्य बड़े पैमाने पर आयुष चिकित्सकों द्वारा प्राप्त नैदानिक परिणामों के बारे में जानकारी एकत्र करना है।

आयुष संजीवनी ऐप के तीसरे संस्करण के बारे में:

- आयुष संजीवनी ऐप के तीसरे वर्जन से बिना लक्षण तथा हलके और मध्यम लक्षण वाले कोविड रोगियों के उपचार में आयुष 64 और कबासुरा कुदिनीर औषधि सहित आयुष के अन्य उपायों की प्रभावकारिता का अध्ययन किया जा सकेगा।
- पहला संस्करण मई 2020 में लॉन्च किया गया था।
- इसे आयुष मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है।
- आयुष 64 आयुर्वेदिक विज्ञान में केंद्रीय अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित एक पॉली-हर्बल फॉर्मूलेशन है। आयुष 64 बिना लक्षण, हल्के और मध्यम COVID-19 संक्रमण के उपचार में उपयोगी है। प्रारंभ में मलेरिया के लिए वर्ष 1980 में दवा विकसित की गई थी।
- **कबासुरा कुदिनीर** सिद्ध चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक पारंपरिक सूत्रीकरण है। यह सामान्य श्वसन स्वास्थ्य के उपचार में उपयोगी है।

संबंधित पहल:

- आय्ष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र
- राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM): भारत सरकार आयुष चिकित्सा प्रणाली के विकास और प्रचार के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से NAM की केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रही है।
- हाल ही में, सरकारी अधिसूचना ने आयुर्वेद के स्नातकोत्तर मेडिकल छात्र द्वारा विशिष्ट सर्जिकल प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध किया है।

नए IT नियम 2021 में ट्रेसबिलिटी प्रावधान

चर्चा में क्यों?

• हाल ही में, फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने नए IT नियम 2021 में ट्रेसबिलिटी प्रावधान को च्नौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है।









ट्रेसिबिलिटी प्रावधान:

- ट्रेसबिलिटी प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का एक हिस्सा है।
- दिशानिर्देशों के अनुसार, संदेश सेवा प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों को अदालत या सक्षम प्राधिकारी के आदेश के आधार पर सूचना के पहले प्रवर्तक की पहचान करनी चाहिए।
- व्हाट्सएप के अनुसार, मैसेजिंग ऐप्स के चैट को 'ट्रेस' करने की आवश्यकता व्हाट्सएप पर भेजे गए हर एक संदेश का फिंगरप्रिंट रखने के लिए कहने के बराबर है, जो एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ और मौलिक रूप से लोगों के निजता के अधिकार को कमजोर कर देगा।
- व्हाट्सएप ने पुट्टस्वामी जजमेंट 2017 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि ट्रेसबिलिटी प्रावधान असंवैधानिक है और लोगों के निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है।
- एंड-ट्-एंड एन्क्रिप्शन यह सुनिश्चित करता है कि प्रेषक और रिसीवर को छोड़कर कोई भी संदेश को नहीं पढ़ सकता है। इसमें व्हाट्सएप भी शामिल है।

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 माध्यमिक या अधीनस्थ कानून है जो भारत के मध्यवर्ती दिशानिर्देश नियम 2011 को बदलता है। 2021 के नियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 से उपजी हैं और मध्यवर्ती नियम, 2018 और डिजिटल मीडिया के लिए OTT विनियमन और आचार संहिता मसौदे का एक संयोजन हैं।

बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

• कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बागवानी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP) शुरू किया।



प्रमुख बिंदु

क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP) के बारे में:

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के **राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड** (NHB) द्वारा कार्यान्वित, एक केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम CDP का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए पहचाने गए बागवानी समूहों को बढ़ाना और विकसित करना है।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 53







बागवानी क्लस्टर की पहचान की है, जिनमें से 12 को कार्यक्रम के पायलट लॉन्च के लिए चुना गया है।

- CDP से लगभग 10 लाख किसानों और मूल्य शृंखला के संबंधित हितधारकों को लाभ होगा।
- सभी 53 क्लस्टर में लागू होने पर CDP से 10,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है।



भारत में बागवानी क्षेत्र:

- भारत विश्व स्तर पर बागवानी फसलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो दुनिया के सब्जियों और फलों के उत्पादन का लगभग 12% है।
- भारत केला, आम, अनार, एसिड लाइम, आंवला और सपोटा जैसे फलों के उत्पादन में अग्रणी है।

हाल ही में उठाए गए कदम:

- मंत्रालय ने 'MIDH-मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर' के लिए वर्ष 2021-22 के लिए 2250 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ आवंटन प्रदान किया है।
- MIDH बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

NCPCR ने ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल "बाल स्वराज (Covid देखभाल)" की शुरुआत की

चर्चा में क्यों?

• राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 109 के अंतर्गत एक निगरानी प्राधिकरण के रूप में अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए और COVID-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित बढ़ती समस्या को देखते हुए देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल "Bal Swaraj (COVID-Care Link)" तैयार किया है।









"बाल स्वराज" के बारे में:

- आयोग का यह पोर्टल देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऑन लाइन ट्रैकिंग तथा डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग व्यवस्था के उददेश्य से बनाया गया है।
- आयोग ने इस पोर्टल के उपयोग को COVID-19 के दौरान माता-पिता या उनमें से किसी एक को खो देने वाले बच्चों की ट्रैकिंग के लिए बढ़ाया है और संबंधित अधिकारी/ विभाग द्वारा ऐसे बच्चों का डाटा अपलोड करने के लिए "COVID-Care" के नाम से लिंक प्रदान किया है।

NCPCR के बारे में:

• राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) संसद के एक अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005 द्वारा स्थापित एक भारतीय वैधानिक निकाय है। आयोग भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है। आयोग ने 5 मार्च 2007 को कार्य करना श्रू किया।

NITI आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 जारी किया

चर्चा में क्यों?

- NITI आयोग ने **सतत विकास लक्ष्य (SDG) इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21** का **तीसरा संस्करण** जारी किया।
- NITI आयोग ने 'SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21: पार्टनरशिप्स इन द डिकेड ऑफ एक्शन' शीर्षक रिपोर्ट जारी की।
- इंडेक्स 2030 SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति का दस्तावेज है।
- भारत में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विकसित SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 सभी राज्यों और केन्द्र -शासित प्रदेशों की प्रगति को उन 115 संकेतकों पर आंकता है जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (NIF) से जुड़े हैं।
- कुल 115 संकेतक लक्ष्य -17 के बारे में गुणात्मक मूल्यांकन के साथ कुल 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDG) में से 16 को शामिल करते हैं और 70 SDG से जुड़े प्रयोजनों को कवर करते हैं।









कार्यप्रणाली

- SDG इंडिया इंडेक्स प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश के लिए 16 SDG पर लक्ष्य-वार स्कोर की गणना करता है।
- कुल मिलाकर राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश के स्कोर 16 SDG पर उनके प्रदर्शन के आधार पर उप-राष्ट्रीय इकाई के समग्र प्रदर्शन को मापने के लिए गणना किये गये लक्ष्य-वार स्कोर में से निकाले जाते हैं।
- ये स्कोर 0-100 के बीच होते हैं, और अगर कोई राज्य/केन्द्र- शासित प्रदेश 100 का स्कोर प्राप्त करता है, तो यह इस तथ्य को दर्शाता है कि उस राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश ने 2030 के लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। किसी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का स्कोर जितना अधिक होगा, उतनी ही अधिक दूरी तक उसने लक्ष्य हासिल कर लिया होगा।
- राज्यों और केन्द्र- शासित प्रदेशों को उनके SDG इंडिया इंडेक्स स्कोर के आधार पर निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया जाता है:

प्रतियोगी (एस्पीरेंट): 0-49

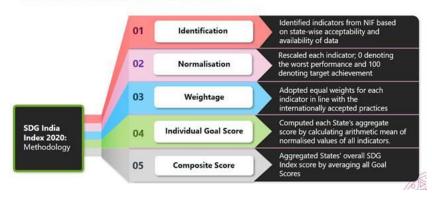
प्रदर्शन करने वाला (परफ़ॉर्मर): 50-64

सबसे आगे चलने वाला (फ्रंट - रनर): 65-99

लक्ष्य पाने वाला (एचीवर): 100

Methodology

Based on globally accepted SDSN methodology









समग्र परिणाम और निष्कर्ष

- देश के समग्र SDG स्कोर में 6 अंकों का सुधार हुआ है 2019 में 60 से बढ़कर 2020-21 में 66 पहुंचा।
- लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में यह सकारात्मक कदम बड़े पैमाने पर लक्ष्य -6 (साफ पानी और स्वच्छता) और लक्ष्य 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा) के बारे में अनुकरणीय देशव्यापी प्रदर्शन से प्रेरित है, जिसमें समग्र लक्ष्य स्कोर क्रमशः 83 और 92 हैं।
- केरल 75 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु 74 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है।
- 52 के न्यूनतम स्कोर के साथ बिहार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले के रूप में उभरा है, इसके बाद झारखंड 56 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है।

GOAL-WISE TOP STATES/UTS

केंद्र शासित प्रदेशों में, चंडीगढ़ 79 के स्कोर के साथ सूची में सबसे ऊपर है।











	75	Kerala	
	74	Himachal Pradesh, Tamil Nadu	
Top-5 States	72	Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Uttarakhand	
	71	Sikkim	
	70	Maharashtra	
	61	Chhattisgarh, Nagaland, Odisha	
	60	Arunachal Pradesh, Meghalaya, Rajasthan, Uttar Pradesh	
Bottom-5 States	57	Assam	
	56	Jharkhand	
	52	Bihar	

नोट: 2019 के स्कोर में सुधार के मामले में मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड 2020-21 में क्रमशः 12, 10 और 8 अंकों की वृद्धि के साथ शीर्ष पर हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मास मीडिया सहयोग पर SCO समझौते को दी मंज्री

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सभी सदस्य देशों के बीच "मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग" के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर और अनुमोदन हेतु अपनी कार्योत्तर मंजूरी दे दी है।
- समझौता, जिस पर जून, 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे, सदस्य राज्यों को मास मीडिया के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं और नए नवाचारों को साझा करने का अवसर प्रदान करेगा।



प्रमुख बिंदु सहयोग के मुख्य क्षेत्र:

- मास मीडिया के माध्यम से सूचना के व्यापक और पारस्परिक वितरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण ताकि अपने देशों के लोगों के जीवन के बारे में ज्ञान को और परिपक्व किया जा सके।
- अपने राज्यों के जनसंचार माध्यमों के







संपादकीय कार्यालयों के साथ-साथ संबंधित मंत्रालयों, एजेंसियों के बीच सहयोग।

- यह टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रमों के प्रसारण और दूसरे पक्षा के राज्य के क्षेत्र में कानूनी रूप से वितरित किए जाने में सहायता करेगा।
- यह समझौता मास मीडिया के क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेगा, मीडिया पेशेवरों को प्रशिक्षण देने में पारस्परिक सहायता प्रदान करेगा और शैक्षिक और वैज्ञानिक अन्संधान संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा।



SCO के बारे में तथ्य: शंघाई सहयोग संगठन या शंघाई पैक्ट, एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है।

- **स्थापना**: 15 जून 2001
- सदस्यः चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान।
- **मुख्यालय:** बीजिंग, चीन
- भारत 2017 में SCO का पूर्ण सदस्य बन गया। इससे पहले, भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त था, जो इसे 2005 में प्रदान किया गया था।

Important News: Defense

अपतटीय गश्ती पोत 'सजग' को भारतीय तटरक्षक में कमीशन किया गया

चर्चा में क्यों?

• राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपतटीय गश्ती पोत (OPV) 'सजग' को भारतीय तटरक्षक (ICG) में शामिल कर सम्द्री हितों की रक्षा के लिए इसे राष्ट्र को समर्पित किया।









- सजग मेक इन इंडिया नीति के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पांच अपतटीय गश्ती पोतो में से तीसरा है।
- OPV सजग का निर्माण मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है।
- अन्य चार OPV भारतीय तटरक्षक पोत (ICGS) सक्षम, ICGS सचेत, ICGS स्जीत और ICGS सार्थक हैं।



भारतीय तटरक्षक के बारे में:

- भारतीय तटरक्षक भारत की एक समुद्री कानून प्रवर्तन और खोज और बचाव एजेंसी है, जिसका क्षेत्राधिकार इसके सन्निहित क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र सहित अपने क्षेत्रीय जल पर है।
- भारतीय तटरक्षक को भारत की संसद के तटरक्षक अधिनियम, 1978 द्वारा स्थापित किया गया था।
- यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है।
- एक बहु-आयामी तटरक्षक के लिए खाका दूरदर्शी **रुस्तमजी समिति** द्वारा तैयार किया गया था। नोट: सरकार के 'मेक इन इंडिया' के विजन के अनुरूप निजी यार्ड सहित देश के भीतर विभिन्न शिपयार्डी में ICG जहाजों का निर्माण किया जा रहा है।
- ICG के बेड़े में कुल 160 जहाज और 62 विमान हैं।

दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची

चर्चा में क्यों?

रक्षा मंत्रालय (MoD) ने 108 वस्तुओं की 'दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची' अधिसूचित की है।



प्रमुख बिंदु

दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची के बारे में:







- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सभी 108 वस्तुओं की खरीद स्वदेशी स्रोतों से की जाएगी।
- इस दूसरी सूची को दिसंबर 2021 से दिसंबर 2025 तक उत्तरोत्तर लागू किए जाने की योजना है।
- इससे आत्मनिर्भरता हासिल करने और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ स्वदेशीकरण को और अधिक बढावा मिलेगा

नोट: अगस्त 2020 में, 101 वस्तुओं वाली 'पहली सकारात्मक स्वदेशीकरण' सूची को अधिसूचित किया गया था। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP 2020) के बारे में:

• रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP 2020), जो रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 (DAP 2016) का स्थान लेती है, पूंजी खरीद प्रक्रिया में स्धार के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा एक ईमानदार प्रयास है।

रक्षा उपकरण का घरेलू उत्पादन बढ़ाने की अन्य पहल:

- रक्षा औद्योगिक कॉरीडोर: प्रमुख "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए भारत ने दो रक्षा औद्योगिक कॉरीडोर, तमिलनाडु में एक और दूसरा उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया।
- घरेलू क्षेत्र के लिए पूँजीगत अधिग्रहण बजट बढ़ाया
- केंद्र सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% और सरकारी मार्ग से 74% से अधिक कर दी है।
- रक्षा भारत स्टार्टअप च्नौती
- आय्ध निर्माणी बोर्डी का निगमीकरण

नोट: रक्षा मंत्रालय द्वारा 'रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति (DPEPP) 2020' का अंतिम संस्करण भी जारी करने की उम्मीद है।

Environment News

जयंती: स्पाइडर क्रिकेट (झींग्र) की एक नई प्रजाति

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के प्राणी विज्ञान विभाग के डॉ रंजना जैसवारा के नेतृत्व में प्राणीविदों की एक टीम ने **छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं** में स्पाइडर क्रिकेट की एक नई प्रजाति की खोज की है।
- देश के प्रमुख गुफा खोजकर्ताओं में से एक, प्रोफेसर जयंत बिस्वास के नाम पर नई उपजाति का नाम जयंती रखा गया।









न्यू स्पाइडर क्रिकेट के बारे में:

- जयंती, जीनस अरकोनोमिमस सॉस्योर, 1897 के तहत पहचाने गए क्रिकेट की बारहवीं उपजातियां या प्रजाति बन गई है।
- नए जयंती नर ध्विन उत्पन्न नहीं कर सकते और उनकी मादाओं के कान नहीं होते।
- नए खोजे गए उपजाति, इंडिमिमस, पुरुष जननांग संरचना के कारण, दो उपजातियों, अरकोनोमिमस और यूराक्नोमिमस से अलग हैं।
- कीड़ों में एक लॉक-एंड-की मॉडल जननांग संरचना होती है जो प्रत्येक उपजाति के लिये अदवितीय होती है।

खोज का महत्व:

- नई प्रजातियां गुफा की दीवारों पर अपने पेट या शरीर के किसी अन्य अंग को पीटकर संचार कर सकती हैं।
- कंपन संचार सिग्नल ट्रांसिमशन के सबसे नरम लेकिन सबसे तेज़ तरीकों में से एक है।
- कंपन संचार के उनके कौशल पर आगे के अध्ययन से मनुष्यों के लिए श्रवण यंत्रों को डिजाइन करने में मदद मिल सकती है जो सबसे शांत संकेतों को पकड़ सकते हैं और एक श्रव्य श्रवण सीमा तक बढ़ा सकते हैं।
- जयंती की खोज के बाद अरकोनोमिमस जाति अब कुल 12 प्रजातियों के नाम से जाना जाएगी। इन प्रजातियों का वितरण (ब्राज़ील से लेकर मलेशिया तक) बह्त व्यापक है।
- भारत में स्पाइडर क्रिकेट की विविधता अभी भी अस्पष्ट है। यह देखते हुए कि भारत में चार जैव विविधता हॉटस्पॉट और सभी हॉटस्पॉट में खाली गुफाएँ होने के कारण यहाँ कई और महत्वपूर्ण खोजों की गुंजाइश है।

Science and Technology

कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस- "ऐम्बिटैग"

चर्चा में क्यों?

• पंजाब में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़ (IIT रोपड़) ने अपनी तरह की पहली अत्याधुनिक IoT डिवाइस- ऐम्बिटैग का विकास किया है, जो खराब होने वाले उत्पादों, वैक्सीन और यहां तक कि शरीर के अंगों व रक्त की ढूलाई के दौरान उनके आसपास का रियल टाइम तापमान दर्ज करती है।

प्रमुख बिंदु

"ऐम्बिटैग" के बारे में

• USB के आकार की डिवाइस, ऐम्बिटैग एक बार रिचार्ज होकर पूरे 90 दिन के लिए किसी भी टाइम जोन में -40 से +80 डिग्री तक के वातावरण में निरंतर तापमान दर्ज करती है।









- डिवाइस को प्रौद्योगिकी नवाचार हब AWaDH (कृषि एवं जल तकनीकी विकास हब) और उसके स्टार्टअप स्क्रैचनेस्ट के तहत विकसित किया गया है।
- AWaDH भारत सरकार की एक परियोजना है।
- यह डिवाइस ISO 13485:2016, EN 12830:2018, CE और ROHS से प्रमाणित है। नोट: ऐसी डिवाइसों को भारत में सिंगापुर, हॉन्गकॉन्ग, आयरलैंड और चीन जैसे दूसरे देशों से बड़ी मात्रा में आयात किया जा रहा है।

IFFCO ने "दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड" लॉन्च किया

चर्चा में क्यों?

• इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO) ने पारंपरिक यूरिया के विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने के लिए एक पोषक तत्व "दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड" लॉन्च किया।



प्रमुख बिंदु नैनो यूरिया के बारे में:

- फसलों के पोषक तत्वों की दक्षता में सुधार के लिए नैनो-प्रौद्योगिकी से उत्पादित यूरिया को नैनो यूरिया कहा जाता है।
- नैनो यूरिया लिक्विड को पारंपरिक यूरिया को बदलने के लिए विकसित किया गया है और यह इसकी आवश्यकता को कम से कम 50% तक कम कर सकता है।
- परंपरागत यूरिया पौधों को नाइट्रोजन देने में 30-40 प्रतिशत प्रभावी है, जबिक नैनो यूरिया लिक्विड की प्रभावशीलता 80 प्रतिशत से अधिक है।



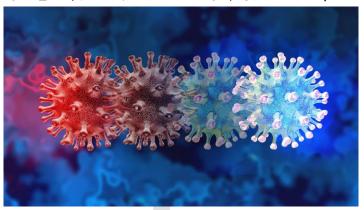




WHO ने भारत में पाए जाने वाले पहले COVID -19 वेरिएंट का नाम 'कप्पा' और 'डेल्टा' के रूप में दिया

चर्चा में क्यों?

• विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने घोषणा की कि भारत में पहली बार पहचाने गए COVID-19 के B.1.617.1 और B.1.617.2 वेरिएंट को क्रमशः 'कप्पा' और 'डेल्टा' नाम दिया गया है।



प्रमुख बिंदु

• वे मौजूदा वैज्ञानिक नामों को प्रतिस्थापित नहीं करेंगे, लेकिन उनका उद्देश्य वेरिएंट ऑफ़ कंसर्न्स (VOCs) एंड वेरिएंट ऑफ़ इंटरेस्ट (VOIs) की सार्वजनिक चर्चा में मदद करना है।

अन्य COVID-19 वेरिएंट:

- B.1.1.7 COVID-19 स्ट्रेन जिसका पहली बार UK में पता चला था, उसे 'अल्फा' के नाम से जाना जाएगा।
- अमेरिका में पाए गए COVID-19 स्ट्रेन 'एप्सिलॉन' और 'आईओटा' हैं।
- दक्षिण अफ्रीका में पाए गए B.1.351 वेरिएंट को अब 'बीटा' कहा जाता है।
- P.1 वैरिएंट जो सबसे पहले ब्राज़ील में पाया गया वह 'गामा' है और P.2 वैरिएंट 'जेटा' है।

Award and Honours

नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य कुमार सेन को स्पेन का प्रिंसेस ऑफ ऑस्टुरियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया

चर्चा में क्यों?

• **भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता** अमर्त्य कुमार सेन को **सामाजिक विज्ञान श्रेणी** में स्पेन का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंद्

• अमर्त्य सेन को अकाल पर उनके शोध और मानव विकास के उनके सिद्धांत, कल्याण अर्थशास्त्र और गरीबी के अंतर्निहित तंत्र ने अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया।









• इस पुरस्कार में 50,000 यूरों का नकद पुरस्कार, सिहत जोआन मिरों की प्रतिमा, एक डिप्लोमा और प्रतीक चिन्ह शामिल है।

नोट:

- अमर्त्य सेन ने 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल प्रस्कार जीता।
- उन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

गोपाल रत्न पुरस्कारों का शुभारंभ और उमंग प्लेटफॉर्म के साथ ई-गोपाल ऐप का एकीकरणचर्चा में क्यों?

- मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर गोपाल रत्न पुरस्कारों के शुभारंभ और उमंग प्लेटफॉर्म के साथ ई-गोपाल ऐप के एकीकरण की घोषणा की।
- हर साल पहली जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है।



Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying Government of India



By

Shri Giriraj Singh

(Hon'ble Minister of Fisheries. Animal Husbandry & Dairving)

प्रमुख बिंदु

गोपाल रत्न प्रस्कार के बारे में:

- गोपाल रत्न पुरस्कार मवेशी और डेयरी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हैं।
- पुरस्कार की तीन श्रेणियां हैं i) सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, ii) सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (AIT)
 और (iii) सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी/दुग्ध उत्पादक कंपनी/FPO।







उमंग (UMANG) प्लेटफॉर्म के बारे में:

- यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेस (UMANG), एक मोबाइल ऐप है, जो केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं तक पहुंच के लिए भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक डिजिटल इंडिया पहल है।
- ऐप को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन के साथ विकसित किया गया था और नवंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। **ई-गोपाल ऐप के बारे में**:
- ई-गोपाल ऐप (उत्पादक पशुधन के माध्यम से धन का सृजन), एक व्यापक नस्ल सुधार बाज़ार और किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए सूचना पोर्टल, को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया था।

डेयरी क्षेत्र से जुड़ी अन्य पहल:

- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम
- डेयरी विकास पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2022
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन
- पाशु-आधार





ऑपरेशन फ्लड (श्वेत क्रांति) के बारे में:

- ऑपरेशन फ्लंड, 13 जनवरी 1970 को शुरू किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम और भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की एक ऐतिहासिक परियोजना।
- ऑपरेशन फ्लड वह कार्यक्रम है जिसके कारण "श्वेत क्रांति" हुई।
- वर्गीज क्रियन को भारत में "श्वेत क्रांति के जनक" के रूप में जाना जाता है।

नोट: भारत डेयरी देशों में एक वैश्विक लीडर है और 2019-20 के दौरान 198.4 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया। वर्तमान में, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, जिसका वैश्विक उत्पादन 22% है।

WHO ने हर्षवर्धन को 'WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार' से सम्मानित किया

प्रस्कार'

चर्चा में क्यों?

• विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्ष वर्धन को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए 'WHO महानिदेशक विशेष मान्यता







से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- श्री वर्धन को ई-सिगरेट और गर्म तंबाक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्कार दिया गया।
- उनके नेतृत्व ने **ई-सिगरेट और गर्म तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2019 के राष्ट्रीय कानून** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।





• WHO ने मध्य प्रदेश स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ और उत्तर प्रदेश तंबाकू नियंत्रण कक्ष को दक्षिण पूर्व क्षेत्र श्रेणी में विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रस्कार से भी सम्मानित किया है।

नोट: विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 31 मई 2021 को मनाया गया।

New Appointments

आश्रिता वी ओलेटी भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनीं

चर्चा में क्यों?

• **भारतीय वायु सेना (IAF) की अधिकारी आश्रिता वी ओलेटी** देश की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बन गई हैं।



प्रमुख बिंदु

- कर्नाटक की मूल निवासी आश्रिता वी ओलेटी ने पायलट स्कूल में एक साल का कोर्स पूरा करने के बाद 43वें फ्लाइट टेस्ट कोर्स के तहत स्नातक किया है।
- ओलेटी सशस्त्र बलों में शामिल होने से पहले विमान और हवाई प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होंगी।







नोट: मेडिकल विंग को छोड़कर जिसमें महिलाएं दशकों से सेवा कर रही हैं, सेना में 6,807 महिला अधिकारी हैं, IAF में 1,607 और नौसेना में 704 महिला अधिकारी हैं। प्रतिशत के संदर्भ में, महिलाएं अभी भी सेना का एक छोटा हिस्सा हैं- सेना का 0.56%, वायु सेना का 1.08% और नौसेना का 6.5%।

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा ने NHRC के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला

चर्चा में क्यों?

• न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा (सेवानिवृत्त) ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला।



प्रमुख बिंदु

• अरुण कुमार मिश्रा अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के बारे में: यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार 12 अक्टूबर 1993 को गठित एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है।

जगजीत पवाडिया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित

चर्चा में क्यों?

- भारत के पूर्व नारकोटिक्स कमिश्नर जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (INCB) का अध्यक्ष चुना गया है।
- वह कॉर्नेलिस पी डी जॉनचेरे का स्थान लेंगी।









- जगजीत पवाडिया संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय हैं और इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला हैं।
- वह 2015 से INCB की सदस्य हैं। वह 2016 में बोर्ड की पहली उपाध्यक्ष चुनी गई।

अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (INCB) के बारे में:

- INCB एक स्वतंत्र, अर्ध-न्यायिक विशेषज्ञ निकाय है, जिसकी स्थापना 1961 के नारकोटिक ड्रग्स पर एकल कन्वेंशन द्वारा दो निकायों: स्थायी केंद्रीय नारकोटिक्स बोर्ड और ड्रग पर्यवेक्षी निकाय को मिलाकर की गई थी।
- इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया है।

Schemes

युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा (YUVA) - प्रधानमंत्री योजना

चर्चा में क्यों?

 शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा (YUVA) -प्रधानमंत्री योजना की श्रुआत की।

प्रमुख बिंद्

युवा -YUVA (युवा, आगामी और बह्मुखी लेखक) योजना के बारे में:

 यह युवा और नवोदित लेखकों (30 वर्ष से कम आयु) को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है, जिससे पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके व वैश्विक स्तर पर भारत और भारतीय लेखन को प्रदर्शित किया सके।









• युवा, भारत@75 परियोजना (आजादी का अमृत महोत्सव) का एक हिस्सा है। यह योजना विस्मृत नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, अज्ञात और भूले हुए स्थानों और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका और अन्य विषय वस्तुओं पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को एक अभिनव व रचनात्मक तरीके से सामने लाने के लिए है।

कार्यान्वयन और निष्पादन:

- शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत योजना की कार्यान्वयन एजेंसी होगी।
- इस योजना के तहत तैयार की गई प्रस्तकों का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत करेगा।
- 1 जून से 31 जुलाई, 2021 तक आयोजित होने वाली अखिल भारतीय प्रतियोगिता के जरिए कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा।
- विजेताओं की घोषणा 15 अगस्त, 2021 को की जाएगी।
- य्वा लेखकों को प्रख्यात लेखक/संरक्षक प्रशिक्षित करेंगे।
- संरक्षण के तहत, पांडुलिपियों को प्रकाशन के लिए 15 दिसंबर, 2021 तक पढ़ा जाएगा।
- प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन 12 जनवरी, 2022 को राष्ट्रीय युवा दिवस (युवा दिवस) के अवसर पर किया जाएगा।
- संरक्षण योजना के तहत छह महीने की अविध के लिए प्रत्येक लेखक को 50,000 रुपये प्रति माह की समेकित छात्रवृति का भ्गतान किया जाएगा।

MDM योजना के तहत DBT के माध्यम से मौद्रिक सहायता

चर्चा में क्यों?

• शिक्षा मंत्रालय ने एक विशेष कल्याण उपाय के तौर पर मध्याहन-भोजन (MDM) योजना के सभी पात्र बच्चों के लिए खाना पकाने की लागत घटक के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से मौद्रिक सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंद्

 यह निर्णय बच्चों के पोषण स्तर को सुरक्षित रखने में मदद करेगा और इस चुनौतीपूर्ण महामारी के समय में उनकी प्रतिरक्षा को बनाए रखने में मदद करेगा।









- यह भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) के तहत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम की दर से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की घोषणा के अतिरिक्त है।
- केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को लगभग 1200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करेगी।
- केंद्र सरकार के इस एक बार के विशेष कल्याणकारी उपाय से देश भर के 11.20 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले लगभग 11.8 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे।

मध्याहन भोजन योजना (MDM) के बारे में:

- यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसको 1995 में शुरू किया गया था।
- मध्याहन भोजन योजना भारत में एक स्कूली भोजन कार्यक्रम है जिसे देश भर में स्कूली उम्र के बच्चों की पोषण स्थिति को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।
- यह कार्यक्रम सरकारी सहायता प्राप्त, स्थानीय निकाय, शिक्षा गारंटी योजना, और सर्व शिक्षा अभियान के तहत समर्थित मदरसा और मकतब, और श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित, सरकारी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूलों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए कार्य दिवसों पर मुफ्त लंच की आपूर्ति करता है।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT):

• प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण 1 जनवरी 2013 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सब्सिडी के हस्तांतरण के तंत्र को बदलने का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को सीधे उनके बैंक खातों के माध्यम से सब्सिडी हस्तांतरित करना है।

DBT से जुड़ी अन्य योजनाएं:

• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, PM KISAN (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना), स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राष्ट्रीय आयुष मिशन, अटल पेंशन योजना।







'PM-केयर्स फॉर चिल्ड्रन' योजना

चर्चा में क्यों?

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COVID19 के कारण अनाथ बच्चों के लिए 'PM-केयर्स फॉर चिल्ड्रन' योजना की श्रुआत की।



प्रमुख बिंदु

• COVID19 के कारण माता-पिता दोनों या माता-पिता में से जीवित बचे या कानूनी अभिभावक/दत्तक माता-पिता को खोने वाले सभी बच्चों को 'PM-केयर्स फॉर चिल्ड्रन' योजना के तहत सहायता दी जाएगी।

'PM-केयर्स फॉर चिल्ड्न' योजना के बारे में:

- ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर मासिक वित्तीय सहायता और 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर PM केयर्स से 10 लाख रुपये की राशि मिलेगी
- COVID 19 के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी
- ऐसे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण दिलाने में सहायता की जाएगी और PM केयर्स उस ऋण पर लगने वाले ब्याज का भुगतान करेगा
- ऐसे बच्चों को आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY) के तहत 18 वर्ष की आयु तक 5 लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा और प्रीमियम का भुगतान PM केयर्स द्वारा किया जाएगा

PM केयर्स फंड के बारे में:

- COVID-19 महामारी जैसी किसी भी तरह की आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित राष्ट्रीय निधि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और उससे प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए 'आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (PM केयर्स फंड)' के नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया गया है।
- प्रधानमंत्री, PM CARES कोष के पदेन अध्यक्ष और भारत सरकार के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, निधि के पदेन ट्रस्टी होते हैं।
- PM-केयर्स फंड में दान दी गई रकम पर इनकम टैक्स से 100 फीसदी छूट मिलेगी। यह राहत इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80G के तहत मिलेगी।
- PM-केयर्स फंड में दान भी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) व्यय के रूप में गिना जाएगा।
- PM केयर्स फंड को भी FCRA के तहत छूट मिली है और विदेशों से दान प्राप्त करने के लिए एक अलग खाता खोला गया है।







केरल की स्मार्ट किचन योजना

चर्चा में क्यों?

• केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घोषणा की है कि सचिव स्तर की समिति 10 जुलाई, 2021 तक 'स्मार्ट किचन योजना' के कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें और दिशानिर्देश तैयार करने के लिए तैयार है।



प्रमुख बिंदु

स्मार्ट किचन योजना के बारे में:

- इसका उद्देश्य महिलाओं के घरेलू श्रम के काम के बोझ को कम करना है।
- महिलाओं को किश्त योजनाओं में कम ब्याज दर के साथ उनकी रसोई के नवीनीकरण के लिए सरकार द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा।

Important Days

29 मई, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अंतर्राष्ट्रीय दिवस

चर्चा में क्यों?

• विश्व संगठन के काम में अपने अमूल्य योगदान के लिए वर्दीधारी और नागरिक कर्मियों को श्रद्धांजित देने और संयुक्त राष्ट्र ध्वज के तहत अपनी जान गंवाने वाले शांति सैनिकों को सम्मानित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 29 मई को मनाया जाता है।



प्रमुख बिंदु

- 2021 का विषय "द रोड टू ए लास्टिंग पीस: लेवरेजिंग द पॉवर ऑफ़ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी" है।
- संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2002 में महासभा द्वारा स्थापित किया गया था।







डैग हैम्मरस्कजोल्ड मेडल प्रस्कार:

• संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर तीन भारतीय शांति रक्षक (कॉर्पोरल युवराज सिंह, दो नागरिक शांति रक्षक - इवान माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव) को मरणोपरांत डैग हैम्मरस्कजोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया।

नोट: भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में वर्दीधारी कर्मियों का पांचवां सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, जिसमें 5,500 से अधिक सैन्य और प्लिस शांति अभियानों में कार्यरत हैं।

31 मई, विश्व तंबाकू निषेध दिवस

चर्चा में क्यों?

• तंबाकू के उपयोग से जुड़े जोखिम को उजागर करने के लिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है।

प्रमुख बिंद्

- विश्व तम्बाकू निषेध दिवस 2021 का विषय "किमट टू क्विट" है।
- दुनिया भर में हर साल 31 मई को मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सदस्य राज्यों द्वारा तंबाकू महामारी और इससे होने वाली रोकथाम योग्य मृत्यु और बीमारी की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाया गया था।



राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के बारे में:

• भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) शुरू किया।

Books and Authors

क्रिकेट के दिग्गज रिव शास्त्री की किताब 'स्टारगेजिंग: द प्लेयर्स इन माई लाइफ'

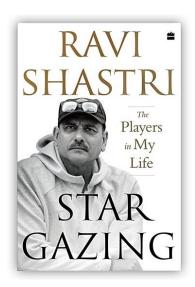
चर्चा में क्यों?

क्रिकेट के दिग्गज, कमेंटेटर और टीम इंडिया के सबसे सफल कोचों में से एक, रिव शास्त्री ने 'स्टारगेजिंग:
 द प्लेयर्स इन माई लाइफ' नामक एक किताब लिखी है।









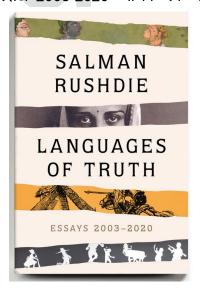
पुस्तक के बारे में:'स्टारगेजिंग: द प्लेयर्स इन माई लाइफ' रवि शास्त्री और खेल पत्रकार अयाज मेमन द्वारा सह-लिखित है और इसके 2021 में जारी होने की उम्मीद है।

- पुस्तक में, शास्त्री दुनिया भर से मिले लगभग 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखते हैं जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया है।
- इसे हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाएगा।

सलमान रुश्दी की पुस्तक "लैंग्वेज ऑफ हुथ: एसेज 2003-2020"

चर्चा में क्यों?

• सलमान रुश्दी ने "लैंग्वेज ऑफ हुथ: एसेज 2003-2020" नामक एक नई किताब लिखी है।



प्रमुख बिंदु

पुस्तक के बारे में:

अपनी नई प्स्तक, "लैंग्वेज ऑफ हुथ: एसेज 2003-2020" में, रुश्दी एक रक्षात्मक कास्टिंग चाल करने







का प्रयास करते हैं।

• उनका सुझाव है कि उनके काम को गलत समझा गया है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है क्योंकि साहित्यिक संस्कृति ब्रियो से भरे कल्पनाशील लेखन से "ऑटोफिक्शन" के विनम्र प्रसन्नता की ओर बदल गई है, जैसा कि ऐलेना फेरेंटे और कार्ल ओवे नोसगार्ड के काम का उदाहरण दिया गया है।

लेखक के बारे में:

• सलमान रुश्दी एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार हैं। उनके दूसरे उपन्यास, 'मिडनाइट्स चिल्ड्रन' (1981) ने 1981 में बुकर पुरस्कार जीता। उनके अधिकांश उपन्यास भारतीय उपमहाद्वीप पर आधारित है।

Sports

एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021

चर्चा में क्यों?

• एशियन एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का 31 वां संस्करण 24 से 31 मई 2021 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

भारत 2 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदक के साथ 4वें स्थान पर रहा।



पदक तालिका

रैंक	राष्ट्र	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
1	कजाकिस्तान	8	6	2	16
2	3ज्बेकिस्तान	7	6	5	18







3	मंगोलिया	3	0	5	8
4	भारत	2	5	8	15

नोट:

- भारत की मेरी कॉम ने 2021 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता।
- एशियन चैंपियनशिप में मैरी कॉम के लिए यह दूसरा रजत है, जिन्होंने 2008 में रजत के अलावा पांच मौकों - 2003, 2005, 2010, 2012 और 2017 में खिताब जीता है।

Miscellaneous

IBF इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के रूप में पुनर्नामित

चर्चा में क्यों?

• OTT सेगमेंट में अपने दायरे का विस्तार करने के लिए, ब्रॉडकास्टर्स के शीर्ष उद्योग निकाय इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (IBF) का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (IBDF) किया गया।



प्रमुख बिंद्

- IBDF सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के रूप में एक स्व-नियामक निकाय (SRB) बनाएगी।
- डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म के लिए स्व-नियामक निकाय का नाम डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल (DMCRC) है।
- DMCRC अपीलीय स्तर पर एक द्वितीय स्तरीय तंत्र है और प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद (BCCC) के समान है, जिसे IBF ने 2011 में रैखिक प्रसारण क्षेत्र के लिए लागू किया था।

इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के बारे में: इसे भारत में टेलीविजन प्रसारकों के एकीकृत प्रतिनिधि निकाय के रूप में भी जाना जाता है। संगठन की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। 250 से अधिक भारतीय टेलीविजन चैनल इससे जुड़े हुए हैं। संगठन को भारत प्रसारण उद्योग के प्रवक्ता के रूप में श्रेय दिया जाता है।

OTT के बारे में: ओवर-द-टॉप (OTT) मीडिया सेवा इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे दी जाने वाली मीडिया सेवा है। OTT केबल, ब्रॉडकास्ट और सैटेलाइट टेलीविजन प्लेटफॉर्म को दरिकनार कर देता है, उन कंपनियों के प्रकार जो परंपरागत रूप से ऐसी सामग्री के नियंत्रक या वितरक के रूप में कार्य करते हैं।







DG NCC मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0

चर्चा में क्यों?

• रक्षा सचिव डॉ अजय कुमार ने महानिदेशालय (DG) राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) मोबाइल प्रशिक्षण एप वर्जन 2.0 की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

DG NCC मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0 के बारे में:

- यह एप COVID-19 महामारी की स्थिति के दौरान NCC कैडेटों को देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करने में सहायता करेगा।
- इसका उद्देश्य NCC से संबंधित बुनियादी जानकारी और संपूर्ण प्रशिक्षण सामग्री को एक मंच पर उपलब्ध कराना है।



नोट: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2020 में प्रशिक्षण के लिए **DG NCC मोबाइल एप वर्जन 1.0** को ऑनलाइन कैडेट प्रशिक्षण में सहायता के लिए शुरू किया था।







RDSO "एक राष्ट्र एक मानक" अभियान के तहत BIS का पहला संस्थान बना जिसे SDO घोषित किया गया है

चर्चा में क्यों?

- उपभोक्ता मामलों के विभाग के अंतर्गत आने वाले भारतीय रेल के संस्थान RDSO (रिसर्च डिजाइन एंड स्टेंडईस ऑरगेनाइजेशन) को "एक राष्ट्र एक मानक" अभियान के तहत BIS (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेंडईस) का पहला SDO (स्टैंडई डेवलिपंग ऑर्गनाइजेशन) संस्थान घोषित किया गया है।
- RDSO ने **BIS SDO मान्यता योजना** के तहत एक मानक विकास संगठन (SDO) के रूप में मान्यता प्राप्त करने की पहल की।

प्रमुख बिंदु

- रेल मंत्रालय का एकमात्र अनुसंधान एवं विकास संगठन RDSO, लखनऊ, देश के प्रमुख मानक तय करने वाले संस्थानों मे से एक है और यह भारतीय रेल के लिए मानक तय करने का काम करता है।
- मान्यता 3 साल के लिए वैध है और वैधता अविध पूरी होने के बाद नवीनीकरण की आवश्यकता होगी।



BIS SDO मान्यता योजना के बारे में:

- भारत सरकार की "एक राष्ट्र एक मानक" की परिकल्पना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मानक संस्थान भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने एक योजना शुरू की है जिसके तहत किसी संस्थान को SDO की मान्यता दी जाती है।
- इस योजना के जिरए BIS का लक्ष्य, अपने विशिष्ट क्षेत्रों में मानकों के विकास के काम में लगे देश के विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध मौजूदा क्षमताओं और विशिष्ट डोमेन में उपलब्ध सकल विशेषज्ञता को एकीकृत करना है और इस तरह देश में जारी सभी मानक विकास गतिविधियों को रूपांतिरत कर "एक विषय पर एक राष्ट्रीय मानक" तैयार करना है।

BIS (भारतीय मानक ब्यूरो) के बारे में:

 भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में काम करने वाला भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। यह भारतीय मानक अधिनियम, 1986 दवारा स्थापित किया गया जो 23 दिसंबर 1986 को प्रभाव में आया था।

BIS की अन्य पहलें:

- उपभोक्ता जुड़ाव के लिए पोर्टल
- BIS-केयर ऐप
- COVID-19 मानक
- गुणवत्ता नियंत्रण आदेश



